

रियल वैल्यू एप्लीकेशन लिमिटेड व अन्य

बनाम

केनरा बैंक व अन्य

5 मई, 1998

[एस. सहगीर अहमद और एम. जगन्नाथ राव, जे. जे.]

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड विनियम, 1987:

धारा-15, 16/22 विनियमन 19 (5)-औद्योगिक कंपनी-उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए याचिका-धन की वसूली के लिए एक नियमित मुकदमा कंपनी के खिलाफ, जो उच्च न्यायालय में भी लंबित है-उसके बाद कंपनी बी. आई. एफ. आर. के समक्ष धारा-15 के तहत अपना संदर्भ पंजीकृत करना और उच्च न्यायालय को इस तथ्य का खुलासा नहीं करना-उच्च न्यायालय ने कंपनी के आचरण की निंदा करते हुए और अस्थायी परिसमापक और प्राप्तकर्ता नियुक्त करने के आदेश देते हुए कहा कि धारा 15 के तहत केवल संदर्भ का पंजीकरण "किसी भी जांच के लंबित होने" के बराबर नहीं है। धारा-16 -माना, उच्च न्यायालय कंपनी के आचरण की निंदा करने में सही था, लेकिन धारा 15 के तहत संदर्भ के पंजीकरण को अमान्य नहीं कहा जा सकता है-संदर्भ के पंजीकरण के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश धारा-22 में निहित

निषेध का उल्लंघन करते हैं। धारा 16 (1) के तहत जांच को संदर्भ के पंजीकरण के साथ-साथ शुरू किया गया माना जाना चाहिए।

क्रानूनों की व्याख्या:

रचना के लिए आंतरिक सहायता-शीर्षक-आयोजित, अध्याय शीर्षक को कठोर खंडों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

अपीलार्थी-कंपनी के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक समापन याचिका दायर की गई थी। कंपनी न्यायाधीश ने एक अस्थायी परिसमापक नियुक्त किया। लेकिन, अपील पर डिवीजन बेंच ने आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

इस बीच अपीलार्थी के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया गया- कंपनी केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। गिरवी रखी गई संपत्तियों का औपचारिक कब्जा लेने के लिए एक रिसीवर नियुक्त करने के लिए उक्त मुकदमे में दायर आवेदन, जो मुकदमे का विषय था, एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन अंतर्वर्ती अपील में डिवीजन बेंच द्वारा अपने दिनांक 28.7.1997 के आदेश द्वारा अनुरोध को मंजूरी दे दी गई थी

अपीलार्थी कंपनी की अपील में रोक प्राप्त करने के बाद स्थगन की मांग करना और अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति का विरोध करने पर चला गया। यह दलील कि यह एक व्यवहार्य इकाई थी। दूसरी ओर, कंपनी ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) से 17.7.1997

पर संपर्क किया और अपना संदर्भ 24.7.1997 पर पंजीकृत कराया, लेकिन इस तथ्य का खुलासा नहीं किया। उस तारीख तक उच्च न्यायालय की खंड पीठ को, जिस तारीख को पीठ ने रोक को खाली करने और अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति की पुष्टि करते हुए एक आदेश पारित किया, यह मानते हुए कि केवल एस के तहत संदर्भ का पंजीकरण। धारा-15 रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धाराओं के तहत "किसी भी जांच के लंबित होने" के बराबर नहीं था। धारा-16 के अन्तर्गत धारा-22 को आकर्षित किया जा सके। इसलिए, पीठ रोक को खाली करने में अपनी शक्तियों के भीतर थी। पीड़ित कंपनी ने इस अदालत के समक्ष 1998 की सी. ए. संख्या 2573 के समक्ष कंपनी की अपील में पारित दिनांक 8.8.1997 के आदेश और 1998 की सी. ए. संख्या 2572 के खिलाफ दायर किया, जिसमें दूसरी खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 28.7.1997 के आदेश को चुनौती दी गई थी। प्राप्तकर्ता की नियुक्ति करने वाली अंतर्वर्ती अपील में उच्च न्यायालय की। 1998 की सी. ए. सं. 2574 कामगार (इंजीनियरिंग कामगार संघ) द्वारा दिनांक 8.8.1998 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था।

प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता-कंपनी दोषी थी। उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यों का दमन, जैसे कि उसने न्यायालय को बी. आई. एफ. आर. से संपर्क करने और संदर्भ पंजीकृत कराने के बारे में

सूचित किए बिना स्थगन लिया, और कंपनी द्वारा तथ्यों के दमन और इसकी व्यवहार्यता के संबंध में उसके द्वारा की गई विरोधाभासी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, बी. आई. एफ. आर. के संदर्भ को दूषित और 'धोखाधड़ी' के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, बी. आई. एफ. आर. के सभी परिणामी आदेशों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि एक बार संदर्भ पंजीकृत हो गया था। एस के तहत धारा-15 अधिनियम को ध्यान में रखते हुए बी. आई. एफ. आर. द्वारा 24.7.1997 पर अधिनियम की धारा-22, उच्च न्यायालय की संबंधित खंड पीठों को 28.7.1997 और 8.8.1997 दिनांकित आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।

अपीलों को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय द्वारा

अभीनिर्धारित: 1.1 यह नहीं कहा जा सकता है कि एस के तहत संदर्भ। धारा-15 रूग्ण का औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 और बी. आई. एफ. आर. द्वारा इसका पंजीकरण कंपनी के किसी भी आचरण के कारण खराब हो गया। उच्च न्यायालय के समक्ष। समान रूप से, संदर्भ पर बी. आई. एफ. आर. द्वारा पारित बाद के आदेशों को उस कारण से अमान्य नहीं कहा जा सकता है। [179 -जी]

1.2 यह सच है कि एक ओर उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी एक रिसीवर और एक अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति का विरोध कर रहा था

यह तर्क देते हुए कि यह एक व्यवहार्य इकाई थी, जबकि दूसरी ओर, इसने [1998] 3 एस. सी. आर. से संपर्क किया था। बी. आई. एफ. आर. ने इसे बीमार कंपनी घोषित करने की मांग करते हुए अपना संदर्भ पंजीकृत कराया और 8.8.1997 तक उच्च न्यायालय को इस तथ्य का खुलासा नहीं किया। यह अपीलार्थी का आचरण निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के लिए बहुत अनुचित था, और इसलिए, उच्च न्यायालय ने ठीक ही इसकी निंदा की थी। न्यायालय को अंधेरे में रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया था। लेकिन, जहां तक बी. आई. एफ. आर. का संबंध है, उसके सामने तथ्यों का कोई दमन नहीं था। बी. आई. एफ. आर. को सूचित किया गया था कि कंपनी की तरफ और मूल तरफ। अपीलार्थी का आचरण-कंपनी इससे पहले कि उच्च न्यायालय बी. आई. एफ. आर. के समक्ष संदर्भ के पंजीकरण को गलत नहीं बना सका। [179 -बी-ई]

2.1 औद्योगिक बोर्ड और वित्तीय पुनर्निर्माण विनियम, 1987 के विनियम 19 में संशोधन के बाद, डब्ल्यू. ई. एफ. 24.3.1994, एक बार संदर्भ पंजीकृत हो जाने के बाद और जब एक बार सूचना देने वाले से सूचना/दस्तावेजों के लिए कॉल करना अनिवार्य हो जाता है और ऐसा निर्देश दिया जाता है, तो बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 16 (1) के तहत जांच धारा 22 के उद्देश्यों के

लिए शुरू की जानी चाहिए। धारा 22 और उसमें निहित निषेध तुरंत लागू हो जाएंगे। [185 – जी-एच]

औद्योगिक वित्त निगम बनाम। महाराष्ट्र स्टील्स लिमिटेड, (1990) 67 कम्प. मामले 412 (ए. आई. आई.)

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड बनाम नीलिमा स्टील्स लिमिटेड, (1990) 68 कम्प. मामले 201 एपी, और

उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड बनाम। ऋषभ इस्पात लिमिटेड, (1993) 78 कम्प. मामले 264 , स्वीकृत किया गया।

मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम। इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, (1995) 82 कम्प. मामले 485 (राज), अस्वीकृत

बंगाल लैम्प्स लिमिटेड बनाम फर्मानाइट निक्को लिमिटेड, (1991) 72 कॉम। मामले 146 (कैल.), संदर्भित।

2.2. विनियम 19 (5) का पहला भाग कहता है कि संदर्भ, यदि यह है क्रम में, पंजीकृत किया जाएगा। दूसरा भाग कहता है कि एक साथ नोटिस करें सूचना देने वाले से सूचना या दस्तावेजों के लिए कॉल जारी किया जाएगा। संशोधित विनियम 19 (5) का प्रभाव यह है कि किसी भी शाखा से पहले भी बी. आई. एफ. आर. विनियमन 20 (1) के तहत जानकारी के लिए कॉल करने के बारे में सोच सकता है या धारा 16 के साथ पठित विनियमन 21 के तहत, यह अब वास्तविक मूल्य आवेदन

लिमिटेड के तहत अनिवार्य है। विनियमन 19 (5) के बाद के अतीत में, कि जैसे ही कोई संदर्भ पंजीकृत किया जाता है, सूचना देने वाले से तुरंत जानकारी/दस्तावेज मांगे जाएँगे। उस स्तर पर ही अधिनियम का। कड़ाई से बोलते हुए, संशोधन के बाद 24.3.1994 पर विनियमन 19 (5) इसके बाद के भाग अध्याय III और IV में आता है। उन विनियमों के जो धारा 16 के तहत 'पूछताछ' के लिए संदर्भित हैं अधिनियम, अध्याय II के बजाय जो धारा के तहत 'संदर्भों' से संबंधित है। 15 अध्याय शीर्षक को कठोर खंड के रूप में नहीं माना जा सकता है। [185 - ए-बी, ई-एफ]

2.3 में निर्धारित संदर्भ के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए विनियमन, बी. आई. एफ. आर. के लिए एक संदर्भ को अस्वीकार करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा बिना जानकारी/दस्तावेजों के लिए बुलाए या कंपनी या अन्य पक्षों को सुने बिना। जब धारा 16 (1) कहती है कि बी. आई. एफ. आर. संचालन कर सकता है। जांच "इस तरह से जो वह उचित समझे", उक्त शब्दों का उद्देश्य केवल यह बताना है कि बी. आई. एफ. आर. में व्यापक विवेकाधिकार निहित है। धारा 16 (1) के तहत जांच करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है और इससे अधिक कुछ नहीं। वास्तव में, एक बार जब संदर्भ जांच के बाद पंजीकृत हो जाता है, तो यह है। बी. आई. एफ. आर. के लिए जांच करना अनिवार्य है। [183 -बी]

2.4. इसके अलावा, इस अधिनियम का उद्देश्य बीमारों को पुनर्जीवित करना और उनका पुनर्वास करना है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत बंद किए जाने से पहले उद्योग। चाहे कंपनी यह घोषणा करना चाहे कि वह बीमार है या कोई अन्य निकाय इसे बीमार कंपनी घोषित करना चाहे, यह आवश्यक है कि कंपनी अधिनियम के तहत कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सुनवाई की जाए। यह भी देखने का विधायी इरादा है कि बी. आई. एफ. आर. द्वारा इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले परिसंपत्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, क्योंकि कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचे जाने या कंपनी को बंद करने की स्थिति में बाद में यथास्थिति को बहाल करना वास्तव में मुश्किल हो सकता है। [183 -डी]

3. इस मामले के तथ्यों पर, 28.7.1997 और 8.8.1997 दिनांकित आदेश बी. आई. एफ. आर. की कार्यवाही 24.7.1997 पर विनियम 19 (5) के दूसरे भाग के चरण में पहुंचने के बाद उच्च न्यायालय की कार्यवाही पारित की गई है, अर्थात् जब संशोधित विनियम 19 (5) के अनुसार कार्यवाही धारा 16 (1) के तहत जांच के चरण में पहुंच गई। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि उक्त आदेश अवैध हैं और अधिनियम की धारा 22 में निहित निषेध का उल्लंघन करते हैं, और इसलिए, उन्हें अलग कर दिया जाता है। [186 -बी-सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2572/1998

बम्बई उच्च न्यायालय [1998] 3 एस. सी. आर. के दिनांकित आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से 1997 के वाद सं. 82 में प्रस्ताव सं. 120/97 की सूचना में ए. सं. 56/97 में प्रस्ताव सं. 421/97 की सूचना में।

सोली जे. सोराबजी, भारत के महान्यायवादी, हरीश एन. साल्वे और जय साल्वा सी. ए. सं. में अपीलार्थियों के लिए साल्वा। 2572 और 2573/98।

सी. ए. नं. में अपीलार्थी के लिए एस. वसीम ए. कादरी और जन कल्याण दास। 2574/98

अल्ताफ अहमद, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, प्रदीप दीवान, सुश्री प्रवीणा सी. ए. संख्या 2572/98 में प्रत्यर्थी के लिए गौतम और प्रमोद बी. अग्रवाल।

सी. ए. सं. 2573/98 और सी. ए. सं. में उत्तरदाताओं के लिए भारत संगाल। 2574/98

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

एम. जगन्नाथ राव, जे. सभी विशेष मामलों में विशेष छूट प्रदान की गई याचिकाओं को छोड़ दें।

एसएलपी (सी) संख्या 14327/1997 से उत्पन्न सिविल अपील 'रियल वैल्यू एप्लायंसेज लिमिटेड' द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के 28.7.1997 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो एक डिवीजन बेंच द्वारा एक अंतरिम अपील में औपचारिक रूप से लेने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया गया था। बंधक संपत्तियों का कब्जा, जो मूल पक्ष पर उक्त उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित 1997 के मुकदमा संख्या 82 का विषय है। प्रतिवादी केनरा बैंक, जो मुकदमे में वादी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपये की राशि का दावा कर रहा है। 24.12.1996 को इसका बकाया 23.67 करोड़ (लगभग) था। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 10.1.1997 में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच द्वारा 20.12.1996 को कार्यवाही को समाप्त करने में दिए गए अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति पर रोक के मद्देनजर रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।

सिविल अपील (एसएलपी (सी) संख्या 14750/1997 से उत्पन्न) अपीलकर्ता कंपनी द्वारा 1996 की अपील संख्या 1193 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक अन्य डिवीजन बेंच दिनांक 8.8.1997 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसके द्वारा आदेश दिया गया था। कंपनी पक्ष के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 18.10.1996 को एक अनंतिम

परिसमापक की नियुक्ति की पुष्टि की गई। जिससे 20.12.96 के पहले के स्थगन आदेश (कंपनी जज के 18.10.96 के आदेश के संबंध में डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया) को रद्द कर दिया गया। प्रतिवादी वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, लेनदार हैं, जिन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता के खिलाफ 6.8.1996 को समापन याचिका 415/1996 दायर की थी।

सिविल अपील (एसएलपी (सी) संख्या 15736/1997 से उत्पन्न) कामगार (इंजीनियरिंग कामगार संघ) द्वारा एकल न्यायाधीश की नियुक्ति के आदेश की पुष्टि करने वाली कार्यवाही को समाप्त करने में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.8.1997 के खिलाफ दायर की गई है। अनंतिम परिसमापक. वे अपीलकर्ता कंपनी का समर्थन कर रहे हैं।

इसी तरह ये तीन अपीलें उठीं और हमारे सामने आईं। अपीलकर्ता कंपनी ने कंपनी अपील में डिवीजन बेंच के समक्ष कुछ स्थगन लेने के बाद -जिसे अनंतिम परिसमापक नियुक्त करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था -बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत 17.7.1997 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (इसके बाद 'बीआईएफआर' कहा जाएगा) के समक्ष एक संदर्भ प्रस्तुत किया गया था। 1985 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा)। उक्त संदर्भ 24.7.1997 को केस संख्या 97/1997 के रूप में दर्ज

किया गया था। इन अपीलों में उठाया गया मुद्दा यह है कि एक बार संदर्भ 24.7.1997 को बीआईएफआर द्वारा पंजीकृत किया गया था, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच को आदेश पारित नहीं करना चाहिए था 8.8.1997 को इसके द्वारा 24.12.1996 को दी गई अंतरिम रोक को हटा दिया गया और अधिनियम की धारा 22 के आदेश के मद्देनजर, अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति के विद्वान कंपनी न्यायाधीश के दिनांक 18.10.1996 के आदेश की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए थी। इसी तरह, यह तर्क दिया गया है कि सिविल सूट से उत्पन्न होने वाली अंतरिम अपील में एक रिसीवर नियुक्त करने की एक अन्य डिवीजन बेंच का दिनांक 28.7.1997 का आदेश भी अधिनियम की धारा 22 के मद्देनजर था।

हम बता सकते हैं कि मुकदमे से उत्पन्न कार्यवाही में 28.7.1997 को रिसीवर की नियुक्ति के उच्च न्यायालय के आदेश पर इस न्यायालय ने एसएलपी 14327/1997 में 5.8.1997 को रोक लगा दी थी। इसी प्रकार, कार्यवाही को समाप्त करने से उत्पन्न कार्यवाही में उच्च न्यायालय के दिनांक 8.8.1997 के आदेश पर रोक हटा दी गई और अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति करने वाले कंपनी न्यायाधीशों के आदेश की पुष्टि करने पर एसएलपी 14750/1997 में 12.8.1997 को रोक लगा दी गई और आगे यह आदेश दिया गया कि अनंतिम परिसमापक कोई और कदम नहीं उठाएगा।

ध्यान देने योग्य एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 10.11.1997 को एसएलपी 14327/1997 में, इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, -दोनों पक्षों को सुनने के बाद, "बीआईएफआर को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए एसएलपी को स्थगित कर दिया। हालांकि, यह न्यायालय, अपीलकर्ता-कंपनी को निर्देश दिया कि बीआईएफआर की पिछली मंजूरी के अलावा कंपनी की किसी भी संपत्ति का निपटान या अलगाव या किसी तीसरे पक्ष के हितों का निर्माण न करें और किसी भी आदेश को पारित करने से पहले, बीआईएफआर केनरा बैंक को सुनवाई देगा। इस न्यायालय ने बैंक का एक दावा भी दर्ज किया कि रिसीवर ने संपत्तियों पर औपचारिक कब्जा कर लिया था। निस्संदेह कंपनी ने इस दावे का खंडन किया था। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8.8.97 में कहा था अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ केनरा बैंक द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को सच माना गया।

इस स्तर पर, कंपनी के आचरण का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसकी पहले ही घोषणा की जा चुकी है, जिसकी बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 8.8.1997 के आदेश में कड़ी आलोचना की थी। हुआ यह था कि 20.12.1996 को डिवीजन बेंच से स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद - एक अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के संबंध में - कंपनी ने 4.11.1996, 2.12.1996 को डिवीजन

बेंच के समक्ष स्थगन प्राप्त किया। 9.12.1996, 18.12.1996, 20.12.1996। 20.12.1996 को मामला 22.7.1997 तक के लिए स्थगित कर दिया गया जब एक हलफनामा दायर किया गया - बिना यह बताए कि कंपनी ने 17.7.1997 को बीआईएफआर से संपर्क किया था - और मामले को 29.7.1997 और फिर 8.8.1997 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 24.7.97 को बीआईएफआर द्वारा संदर्भ के पंजीकरण का तथ्य 8.8.1997 तक उच्च न्यायालय को नहीं बताया गया था। इसलिए, खंडपीठ ने 8.8.1997 से पहले उच्च न्यायालय को इन तथ्यों का खुलासा नहीं करने के लिए अपीलकर्ता के आचरण की आलोचना की। इसके अलावा, उच्च न्यायालय में कंपनी इस दलील पर अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति का विरोध कर रही थी कि यह एक व्यवहार्य इकाई थी, लेकिन जब उसने बीआईएफआर से संपर्क किया, तो यह दावा कर रही थी कि यह एक बीमार उद्योग है। इन विरोधाभासी दलीलों पर उच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी भी सामने आई। बेंच ने अधिनियम की धारा 22 और धारा 16 का उल्लेख किया और महसूस किया कि धारा 15 के तहत केवल संदर्भ का पंजीकरण धारा 16 के तहत "किसी भी जांच के लंबित होने" के बराबर नहीं है और इसलिए, धारा 22 लागू नहीं होती है और इसलिए बेंच ने रोक हटाने और अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति की पुष्टि करने या रिसीवर नियुक्त करने में अपनी शक्तियों के भीतर अच्छी तरह से काम किया। उस संदर्भ में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बंगाल लैप्स लिमिटेड बनाम फुरमैनाइट निक्को लिमिटेड

[1991 (72) कॉम. मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले का पालन किया। मामले 146 (कैल.)] अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों को प्राथमिकता देते हुए, जिन्होंने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था। बेंच ने तब इस आशय के कई निष्कर्ष दिए कि कंपनी ने अपनी लेखांकन प्रक्रियाओं आदि में विभिन्न "अनियमितताओं" या "कदाचार" में लिप्त थी, यह दिखाने के लिए कि यह एक व्यवहार्य इकाई थी और यह दिखाने के लिए कि यह उत्तरदायी नहीं थी। खत्म करना। बैंक द्वारा बताई गई कथित वित्तीय अनियमितताओं और तथ्यों को दबाने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8.8.1997 में दिनांक 20.12.1996 के स्थगन आदेश को हटा दिया और अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति की पुष्टि की। कंपनी के अधिकारियों को अवमानना नोटिस भी जारी किया।

उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत आदेश पारित किए जाने के बाद हुई कुछ बाद की घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। ये घटनाएँ मुख्य रूप से बीआईएफआर द्वारा पारित तीन आदेशों से संबंधित हैं।

(i) 9.9.1997 को, बीआईएफआर ने अपीलकर्ता - कंपनी और केनरा बैंक और आईडीबीआई (जिसे कंपनी से लगभग 38 करोड़ रुपये भी मिलने थे) के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद धारा 16 के तहत आईडीबीआई को निर्देश देते हुए आदेश पारित किया। (2) अधिनियम के 30.6.1997 तक कंपनी की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की जांच और विश्लेषण करने और एक

स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। बैंक को आईडीबीआई को अपनी प्रतिक्रिया या टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था। बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए तर्कों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया

(ii) 24.11.1997 को बीआईएफआर ने यह दर्ज करते हुए आदेश पारित किया कि आईडीबीआई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस आधार पर और प्रस्तुत प्रस्तुतियों के आधार पर, धारा 16 के तहत "कंपनी को एक बीमार उद्योग घोषित किया जाना था"। अधिनियम की धारा 3(ओ)। इसके बाद इसमें कहा गया कि कंपनी के संबंध में अधिनियम की धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट उपायों को अपनाना सार्वजनिक हित में आवश्यक है। इसने तदनुसार धारा 16 के तहत आईडीबीआई को ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। (2) अधिनियम की धारा 17(3) के तहत पुनर्वास रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। कंपनी को धारा 22-ए के तहत अपनी किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करने का निर्देश दिया गया।

(iii) बीआईएफआर द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें 15.12.1997 की तारीख तय की गई थी जिस दिन कंपनी के खिलाफ केनरा बैंक के आरोपों पर सुनवाई की जाएगी। 15.12.1997 को, बीआईएफआर ने बैंक के प्रतिनिधियों को यह कहते हुए सुनने के बाद आगे

के आदेश पारित किए कि कंपनी के खिलाफ बैंक द्वारा लगाए गए आरोपों पर आईडीबीआई ने विचार किया था और आईडीबीआई ने एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की थी और बीआईएफआर आरोपों से संतुष्ट था। कंपनी के खिलाफ बैंक की कार्रवाई - लेखांकन वर्ष में बदलाव और मूल्यहास और ब्याज के प्रावधान के संबंध में और बैलेंस शीट की तैयारी के संबंध में - स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कार्रवाई "विभिन्न प्रावधानों के तहत अनुमेय थी" कंपनी अधिनियम , 1956 और इस प्रकार ये कानून के तहत वैध थे"। कंपनी को अपने पुनरुद्धार/पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया था। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के विवादित आदेशों के बाद बीआईएफआर द्वारा पारित तीन आदेश हैं।

कंपनी द्वारा दायर की गई दो अपीलों में कंपनी की ओर से उपस्थित श्री सोली सोराबजी और श्री हरीश साल्वे द्वारा और तीसरी अपील में श्रमिकों के वकील द्वारा हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि डिवीजन बेंच को दिनांक 25.11.2019 को लगाई गई रोक को नहीं हटाना चाहिए था। 20.12.96 ने न ही अपने आदेश दिनांक 8.8.1997 द्वारा दिनांक 18.10.96 के अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति की पुष्टि की, जब उस तिथि तक, बीआईएफआर द्वारा दिनांक 17.7.1997 के संदर्भ के पंजीकरण के कारण अधिनियम की धारा 22 लागू हो गई थी। 24.7.1997 को. उन्हीं कारणों से, यह तर्क दिया गया कि डिवीजन बेंच मुकदमे की कार्यवाही में दायर

अंतरिम अपील में 28.7.1997 को रिसीवर नियुक्त नहीं कर सकती थी। यह तर्क दिया गया कि इसलिए, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और धारा 22 के तहत शासनादेश के मद्देनजर लागू आदेशों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। श्री सोराबजी ने यह तर्क देने के लिए उच्च न्यायालयों के कई फैसलों का हवाला दिया कि धारा 22 की प्रयोज्यता के प्रयोजनों के लिए संदर्भ का पंजीकरण पर्याप्त था। यह तर्क दिया गया कि अब मामले बीआईएफआर के समक्ष अधिनियम की धारा 17(3) के चरण में पहुंच गए हैं और इसलिए, रिसीवर या अनंतिम परिसमापक को बहाल करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। हमारे संज्ञान में यह भी लाया गया कि उच्च न्यायालय ने माफी मांगने के बाद अपने आदेश दिनांक 13.2.1998 द्वारा अवमानना कार्यवाही को समाप्त कर दिया था।

दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री अल्ताफ अहमद ने तर्क दिया कि धारा 22 के संबंध में अपीलकर्ताओं का तर्क सही हो सकता है, लेकिन अपीलकर्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष तथ्यों को छिपाने का दोषी था जैसा कि बताया गया है। आदेश दिनांक 8.8.1997. इसने न्यायालय को यह बताए बिना कि वह या तो संपर्क कर रहा है या उसने बीआईएफआर से संपर्क किया है और अपना संदर्भ पंजीकृत कराया है, उच्च न्यायालय के समक्ष स्थगन ले लिया। कंपनी ने अपनी व्यवहार्यता के संबंध में उच्च न्यायालय और बीआईएफआर के

समक्ष विरोधाभासी दलीलें भी दीं। यह आचरण पूर्णतः अशोभनीय था। तथ्यों को दबाने और परस्पर विपरीत दलीलों के कारण, बीआईएफआर के संदर्भ को दूषित और 'धोखाधड़ी' के समान माना जाना चाहिए और इसलिए, बीआईएफआर के सभी परिणामी आदेशों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर, निम्नलिखित बिंदु विचारणीय हैं:

(1) क्या यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय और बीआईएफआर के समक्ष अपीलकर्ता कंपनी द्वारा की गई विपरीत दलीलों और तथ्यों के दमन के कारण उच्च न्यायालय के समक्ष उसका आचरण, - धारा के तहत संदर्भ प्रस्तुत करेगा 15 और संदर्भ का पंजीकरण और बीआईएफआर के बाद के आदेश खराब?

(2) क्या, एक बार जब बीआईएफआर ने विनियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 15 के तहत संदर्भ दिनांक 17.7.97 को 24.7.97 को पंजीकृत कर लिया था, तो उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के लिए 8.8.97 को आदेश पारित करना अनुमत था। स्थगन आदेश दिनांक 20.12.96 और कंपनी की ओर से अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति की पुष्टि करना और यह भी कि क्या उच्च न्यायालय की किसी अन्य डिवीजन बेंच के लिए मुकदमे से उत्पन्न कार्यवाही में 28.7.97 को एक रिसेवर नियुक्त करना स्वीकार्य था, में अधिनियम की धारा 22 को देखें?

बिंदु 1:

यह सच है कि समापन कार्यवाही और सिविल मुकदमे में, अपीलकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि यह एक व्यवहार्य इकाई थी और न तो रिसीवर और न ही अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया जा सकता था। अपीलकर्ता एक ओर डिवीजन बेंच के समक्ष स्थगन की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसने 17.7.97 को बीआईएफआर से संपर्क किया और 24.7.97 को एक बीमार कंपनी घोषित करने की मांग करते हुए अपना संदर्भ पंजीकृत कराया। यह भी सच है कि 22.7.97 को स्थगन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अपनी ओर से दायर हलफनामे में, उसने डिवीजन बेंच को यह नहीं बताया था कि उसने 17.7.97 को बीआईएफआर को स्थानांतरित कर दिया था। कंपनी ने 29.7.97 और फिर 8.8.97 तक के स्थगन की मांग की। न तो 22.7.97 को और न ही 29.7.97 को उच्च न्यायालय को बीआईएफआर के समक्ष दायर आवेदन के बारे में और न ही उसके पंजीकरण के बारे में सूचित किया गया। इन तथ्यों का खुलासा 8.8.97 को ही किया गया था

अपीलकर्ता का यह आचरण, हमारे विचार में, निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के लिए बहुत अनुचित था और इसलिए, उच्च न्यायालय ने उचित ही इसका अवमूल्यन किया था। हमारे विचार में, न्यायालय को

अंधेरे में रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस कारण से बीआईएफआर के लिए संदर्भ आवेदन खराब हो जाएगा बीआईएफआर के समक्ष दायर आवेदन से यह स्पष्ट है कि बीआईएफआर को कंपनी पक्ष और मूल पक्ष दोनों तरफ से उच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ की गई कार्यवाही के बारे में सूचित किया गया था। जहां तक बीआईएफआर का सवाल है, इससे पहले तथ्यों को छुपाया नहीं गया था। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता कंपनी का कोई भी आचरण बीआईएफआर के समक्ष संदर्भ के पंजीकरण को खराब कैसे बना सकता है। यदि कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त किया गया था, तो यह निश्चित रूप से प्रतिवादी के लिए खुला था कि वह उच्च न्यायालय से ऐसे आदेशों को वापस लेने के लिए कह सके। ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसलिए, हम उत्तरदाताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि अधिनियम की धारा 15 के तहत संदर्भ और बीआईएफआर द्वारा उसका पंजीकरण उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी के किसी भी आचरण के कारण खराब हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि संदर्भ पर बीआईएफआर द्वारा पारित बाद के आदेशों को भी उस आधार पर अमान्य नहीं कहा जा सकता है। उत्तरदाताओं का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है। बिंदु 1 उत्तरदाताओं के विरुद्ध रखा गया है।

बिंदु 2:

इस अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में इस बिंदु के तहत कानूनी मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है।

इसलिए, हम अधिनियम और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों और अधिनियम में अध्यायों के शीर्षकों और विनियमों में अध्यायों के शीर्षकों का उल्लेख करेंगे।

अधिनियम के अध्याय III में धारा 15 से धारा 22 ए तक शामिल है और इसका शीर्षक "संदर्भ, पूछताछ और योजनाएं" है। अधिनियम की धारा 15 धारा 15 के उप-खंड (1) के तहत औद्योगिक कंपनी द्वारा या केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक या राज्य सरकार या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या राज्य द्वारा 'बोर्ड के संदर्भ' को संदर्भित करती है। स्थानीय संस्थान या अनुसूचित बैंक। धारा 16 में 'बीमार औद्योगिक कंपनियों के कामकाज की जांच' और जांच के बाद इकाई को बीमार उद्योग घोषित करने का उल्लेख है। धारा 17 कंपनी को 'जांच पूरी होने पर उचित आदेश देने के लिए बोर्ड की शक्तियों' से संबंधित है ताकि उचित समय के भीतर उसका शुद्ध मूल्य उसके संचित घाटे से अधिक हो सके या ऑपरेटिंग एजेंसी को दिए गए तरीके से एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया जा सके। धारा 18 में धारा 19 'वित्तीय सहायता देकर पुनर्वास' से संबंधित है। धारा 20 में

औद्योगिक इकाई को बंद करने का उल्लेख है यदि यह संभावना नहीं है कि कंपनी अपनी कुल संपत्ति को अपने संचित घाटे से अधिक करने में सक्षम होगी। अधिनियम की धारा 22, जिसके बारे में हम यहां चिंतित हैं, 'कानूनी कार्यवाही, अनुबंध आदि के निलंबन' से संबंधित है। जहां ' धारा 16 के तहत एक जांच लंबित है या धारा 17 के तहत कोई योजना तैयारी या विचाराधीन है या एक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन के तहत है या जहां अपीलीय प्राधिकारी (एएआईएफआर) के समक्ष धारा 25 के तहत अपील लंबित है।

इस संदर्भ में, कई उच्च न्यायालयों में जो मुद्दा उठाया गया है, वह यह है कि अधिनियम के तहत बीआईएफआर द्वारा एक संदर्भ के पंजीकरण मात्र से उन सभी कार्यवाहियों का स्वतः समापन नहीं होगा जो या तो सिविल अदालतों में या अदालतों में लंबित हैं। कंपनी न्यायालय आदि इसकी संपत्तियों के विरुद्ध। यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 22 को लागू करने के लिए, बीआईएफआर को - धारा 15 के तहत संदर्भ के पंजीकरण के बाद - अपना दिमाग लगाना चाहिए और धारा 16 के तहत जांच करना और नोटिस जारी करना आवश्यक समझना चाहिए। प्रभावित पक्षों का संदर्भ, जिन्हें सुना जाना आवश्यक है, और केवल तभी यह कहा जा सकता है कि एक 'जांच' लंबित है। जब तक कोई जांच लंबित न हो

तब तक कार्यवाही आदि पर वैधानिक रोक नहीं लगाई जा सकती, जैसा कि अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान है।

उपरोक्त बिंदु को समझने के लिए अधिनियम की धारा 16 के उप-खंड (1) से (4) और धारा 22(1) का संदर्भ लेना आवश्यक है। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

"एस. 16: बीमार औद्योगिक कंपनियों के कामकाज की जांच - (1) बोर्ड ऐसी जांच कर सकता है जो यह निर्धारित करने के लिए उचित समझे कि क्या कोई औद्योगिक कंपनी बीमार औद्योगिक कंपनी बन गई है-

(ए) धारा 15 के तहत ऐसी कंपनी के संबंध में एक संदर्भ प्राप्त होने पर; या

(बी) ऐसी कंपनी के संबंध में प्राप्त जानकारी पर या कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में अपने स्वयं के ज्ञान पर।

(2) बोर्ड, यदि उप-धारा (1) के तहत किसी जांच के शीघ्र निपटान के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो किसी भी ऑपरेटिंग एजेंसी को ऐसे मामलों के संबंध में जांच करने और रिपोर्ट बनाने के लिए आदेश दे सकता है। आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) बोर्ड या जैसा भी मामला हो, संचालन एजेंसी अपनी जांच यथासंभव शीघ्रता से पूरी करेगी और जांच शुरू होने के साठ दिनों के भीतर

जांच पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। स्पष्टीकरण -इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड द्वारा किसी संदर्भ या जानकारी की प्राप्ति पर या बोर्ड द्वारा लिखित रूप में अपने स्वयं के ज्ञान पर एक जांच शुरू की गई मानी जाएगी।

(4) जहां बोर्ड उप-धारा (1) के तहत या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) के तहत किसी औद्योगिक कंपनी की जांच करना या जांच कराना उचित समझता है, तो वह ऐसा कर सकता है। कंपनी के वित्तीय और अन्य हितों की सुरक्षा या सार्वजनिक हित के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को कंपनी का विशेष निदेशक या विशेष निदेशक नियुक्त करना।

"धारा 22(1): कानूनी कार्यवाही, अनुबंध आदि का निलंबन: जहां किसी औद्योगिक कंपनी के संबंध में, धारा 16 के तहत एक जांच लंबित है या धारा 17 के तहत संदर्भित कोई योजना तैयारी या विचाराधीन है या एक स्वीकृत योजना चल रही है कार्यान्वयन या जहां किसी औद्योगिक कंपनी से संबंधित धारा 25 के तहत अपील लंबित है, तो, कंपनी अधिनियम , 1956 (1956 का 1), या किसी अन्य कानून या औद्योगिक कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख या किसी भी बात के बावजूद, उक्त अधिनियम या

अन्य कानून के तहत प्रभाव रखने वाले अन्य साधन, औद्योगिक कंपनी को बंद करने या औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कार्रवाई या उसके संबंध में रिसीवर की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं (और पैसे की वसूली के लिए या औद्योगिक कंपनी के खिलाफ किसी भी सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए या औद्योगिक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी भी गारंटी के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा या आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी, बिना सहमति के। बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी।"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 22 के अनुसार , यदि " धारा 16 के तहत जांच" लंबित है, तो, कंपनी अधिनियम या किसी अन्य उपकरण आदि में कुछ भी होने के बावजूद , कंपनी के समापन या निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। या कंपनी की संपत्ति के खिलाफ या किसी रिसीवर की नियुक्ति के लिए या धन की वसूली के लिए

या किसी सुरक्षा या किसी गारंटी के प्रवर्तन के लिए कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा - बोर्ड की सहमति के बिना, झूठ बोला जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा। या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा। धारा 22 ए बोर्ड को कुछ सशर्त आदेश पारित करने की अनुमति देती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 16 के उप-खंड (1) में कहा गया है कि बोर्ड ऐसी जांच कर सकता है जो यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त हो कि क्या कोई औद्योगिक कंपनी बीमार औद्योगिक इकाई बन गई है - (ए) प्राप्त होने पर धारा 15 या (बी) के तहत एक संदर्भ प्राप्त जानकारी पर या कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में अपने स्वयं के ज्ञान पर। धारा 16 के उप-खंड (2) के तहत, बोर्ड, यदि यह आवश्यक या समीचीन समझता है, तो किसी भी ऑपरेटिंग एजेंसी से पूछताछ करने और उसे रिपोर्ट करने की मांग कर सकता है। उप-खंड (3) के तहत, बोर्ड या संचालन एजेंसी को जांच शुरू होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का प्रयास करना है। उप-खंड (3) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण से पता चलता है कि उप-खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, यानी 60 दिनों की अवधि की गणना के लिए, बोर्ड या किसी संदर्भ द्वारा रसीद पर एक जांच शुरू की गई मानी जाएगी। या जानकारी या अपने स्वयं के ज्ञान पर बोर्ड द्वारा लिखित रूप में कम कर दी गई है। उप-खंड (4) के तहत, जब बोर्ड धारा 16 के उप-खंड (1) या (2) के तहत जांच करना उचित समझता है,

तो वह (1994 के अधिनियम 12 द्वारा 'शब्द' हटा दिया गया है) कर सकता है। एक या अधिक निदेशकों आदि की नियुक्ति करें।

अधिनियम की धारा 16(1) में 'हो सकता है' शब्द के उपयोग पर भरोसा करते हुए कुछ उच्च न्यायालयों में यह तर्क दिया गया है कि उस धारा में 'हो सकता है' शब्द से पता चलता है कि बीआईएफआर के पास शक्ति है। गुण-दोष पर गौर किए बिना किसी संदर्भ को संक्षेप में अस्वीकार कर दें और यह तभी होता है जब बीआईएफआर धारा 16(1) के तहत गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए संदर्भ लेता है, तब यह कहा जा सकता है कि अनुभाग द्वारा विचार की गई 'जांच' शुरू हो गई है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि बीआईएफआर के समक्ष संदर्भ केवल धारा 15 के तहत पंजीकरण के चरण में है, तो धारा 22 लागू नहीं होती है। हमारी राय में इस विवाद में कोई दम नहीं है। हमारे विचार में, जब धारा 16(1) कहती है कि बीआईएफआर "उस तरीके से जांच कर सकता है जैसा वह उचित समझे", तो उक्त शब्दों का उद्देश्य केवल यह बताना है कि बीआईएफआर के संबंध में व्यापक विवेक निहित है। धारा 16(1) के तहत जांच करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और कुछ नहीं। वास्तव में, एक बार जांच के बाद संदर्भ पंजीकृत हो जाने के बाद, हमारे विचार से, बीआईएफआर के लिए जांच करना अनिवार्य है। यदि कोई विनियमों में निर्धारित संदर्भ के प्रारूप को देखता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कंपनी की संपत्ति,

देनदारियों आदि के व्यापक वित्तीय विवरण के संबंध में पचास से अधिक कॉलम हैं। वास्तव में, बीआईएफआर के लिए यह व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। सूचना/दस्तावेज मांगे बिना या कंपनी या अन्य पक्षों को सुने बिना किसी संदर्भ को सिरे से अस्वीकार कर देना। इसके अलावा, इस अधिनियम का उद्देश्य बीमार उद्योगों को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत समाप्त होने से पहले पुनर्जीवित और पुनर्वास करना है। चाहे कंपनी यह घोषणा चाहती हो कि वह बीमार है या कोई अन्य निकाय उसे बीमार कंपनी घोषित करना चाहता है, यह हमारी राय में, यह आवश्यक है कि अधिनियम के तहत कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले कंपनी को सुना जाए। विधायी उद्देश्य यह भी देखना है कि बीआईएफआर द्वारा इस तरह का कोई भी निर्णय दिए जाने से पहले संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, क्योंकि कंपनी की संपत्तियां बेची जाती हैं, या कंपनी बंद हो जाती है, बाद में स्थिति को बहाल करना वास्तव में मुश्किल हो सकता है। यथा पूर्व. इसलिए, हमारे विचार में, औद्योगिक वित्त निगम बनाम महाराष्ट्र स्टील्स लिमिटेड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय । [1990 67 कॉम्प. केस 412 (सभी)], स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड बनाम नीलिमा स्टील्स लिमिटेड में आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय । [1990 68 कॉम्प. केस 201 (एपी)], उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड बनाम ऋषभ इस्पात लिमिटेड में हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय । [1993] 78 कंप. मामले 264] इस तरह के तर्क को खारिज करने और यह मानने में सही हैं कि जांच के बाद

संदर्भ का पंजीकरण पूरा होते ही जांच शुरू हो गई मानी जानी चाहिए और उस समय से, कंपनी की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई रुकी रहनी चाहिए जैसा कि कहा गया है धारा 22 में बीआईएफआर द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक।

दूसरा विचार यह है कि केवल पंजीकरण धारा 22(1) के प्रयोजनों के लिए " धारा 16(1) के तहत जांच शुरू करना" नहीं है , यह कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बंगाल लैप्स केस (सुप्रा) में और राजस्थान उच्च द्वारा लिया गया है। मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड में न्यायालय । [1995 82 कॉम्प. केस 485 (राजस्थान)]। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर आधारित है।

हम इन विनियमों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के तहत बनाए गए विनियमों के अध्याय II में ' धारा 15 के तहत संदर्भ' शीर्षक है और इसमें विनियमन 19 शामिल है। अध्याय III 'पूछताछ के संबंध में सामान्य प्रावधानों' से संबंधित है और इसमें विनियमन 20 शामिल है, जबकि अध्याय IV में शीर्षक 'पूछताछ के तहत है' है। धारा 16 " में विनियम 21 से 25 शामिल हैं। अध्याय V धारा 17 के तहत कार्यवाही से संबंधित है और इसमें विनियम 26 शामिल है। वर्तमान उद्देश्य के लिए, हम अन्य अध्यायों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं जो बहुत प्रासंगिक नहीं हैं।

बंगाल लैम्प्स लिमिटेड केस (सुप्रा) में कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच -जिस मामले पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 8.8.1997 के आक्षेपित आदेश में भरोसा किया है - यह माना गया है कि विनियम 19 (विनियम के अध्याय II में जो केवल धारा 15 को संदर्भित करता है) के साथ पठित अधिनियम की धारा 15 के तहत संदर्भ के पंजीकरण के चरण में , किसी भी संदर्भित 'जांच' के शुरू होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। अधिनियम की धारा 16 के लिए . इस तरह की जांच को केवल विनियम 21 के साथ पढ़ी गई धारा 16 के चरण में शुरू किया गया माना जा सकता है (विनियम के अध्याय IV में जो धारा 16 को संदर्भित करता है)। उस तर्क पर यह माना गया कि धारा 22 के अनुसार रोक केवल तभी लगाई जा सकती है जब धारा 16(1) की जांच का चरण आ गया हो, न कि संदर्भ के पंजीकरण से संबंधित धारा 15 के चरण पर। इसने आगे कहा कि ऐसा तभी होता है जब बीआईएफआर, यानी बीआईएफआर की बेंच पूछताछ के लिए धारा 16(1) के तहत नोटिस जारी करती है या ऑपरेटिंग एजेंसी को पूछताछ करने के लिए कहती है, - कि 'जांच' शुरू हो गई है, ऐसा कहा जा सकता है। तर्क की यह पंक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत फैसले में भी लागू की गई है। प्रश्न यह है कि क्या यह दृष्टिकोण सही है?

अब, विनियम 19(4) जो धारा 15 से संबंधित है, के लिए आवश्यक है कि एक संदर्भ प्राप्त होने पर, एक पावती जारी की जाए जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाए कि संदर्भ प्राप्त हो गया है 'सत्यापन के अधीन कि संदर्भ क्रम में है'। यदि जांच करने पर संदर्भ सही पाया गया तो उसे विनियम 19(5) के तहत पंजीकृत किया जाएगा। विनियमन 19(5) को हाल ही में 24.3.1994 से संशोधित किया गया है, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख के बहुत बाद की तारीख है। 24.3.1994 से प्रतिस्थापित नया विनियमन 19(5) दो भागों में है और इस प्रकार है:

"रेग. 19(5): यदि जांच करने पर, संदर्भ सही पाया जाता है, तो इसे पंजीकृत किया जाएगा, एक सीरियल नंबर दिया जाएगा और अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा या इसे एक बेंच को सौंप दिया जाएगा। साथ ही, शेष जानकारी/दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, यदि कोई हो, तो मुखबिर से जानकारी मांगी जाएगी।"

पहला भाग कहता है कि संदर्भ, यदि वह क्रम में है, पंजीकृत किया जाएगा। दूसरे भाग में कहा गया है कि साथ ही सूचना देने वाले से जानकारी या दस्तावेज मांगने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

संशोधित विनियम 19(5) का प्रभाव यह है कि इससे पहले कि बीआईएफआर की कोई भी पीठ विनियम 20(1) के तहत या धारा 16 के साथ पढ़े गए विनियम 21 के तहत जानकारी मांगने के बारे में सोच सके, संशोधन के बाद अब यह अनिवार्य है कि जितनी जल्दी हो सके जैसे ही कोई संदर्भ पंजीकृत होता है, सूचनाकर्ता से सीधे सूचना/दस्तावेज मांगे जाएंगे। मुद्दा यह है कि जब ऐसी जानकारी/दस्तावेजों को विनियमन 19(5) चरण में एक साथ मंगाने की आवश्यकता होती है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि धारा 16(1) के तहत एक 'जांच' शुरू हो गई है?

उपरोक्त प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि अधिनियम की धारा 16(1) में प्रयुक्त 'पूछताछ' शब्द का क्या अर्थ है। न्यू स्टैंडर्ड डिक्शनरी के अनुसार, 'पूछताछ' शब्द में आम तौर पर तथ्यों, कारणों, प्रभावों और संबंधों की 'जांच' शामिल है; उसी शब्दकोष के अनुसार 'पूछताछ करना' का अर्थ है 'कुछ खोजने के लिए स्वयं को प्रयास करना। चैंबर्स 20वीं सेंचुरी डिक्शनरी में कहा गया है कि 'पूछताछ करना' शब्द का अर्थ "पूछना, खोजना" है और 'पूछताछ' शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया गया है: "ज्ञान की खोज; जांच: एक प्रश्न"।

चूंकि विनियम 19(5) के उत्तरार्द्ध भाग के तहत यह आवश्यक है कि संदर्भ के पंजीकरण के साथ-साथ सूचनादाता से जानकारी/दस्तावेज मांगे जाएं - हमारी राय में, 'पूछताछ' को माना जाना चाहिए अधिनियम की

धारा 16 के तहत उस चरण में ही शुरू किया गया था, अर्थात् विनियमन 19(5) के दूसरे भाग के चरण में और अब यह कहना स्वीकार्य नहीं है कि ऐसा चरण केवल तभी पहुंचता है जब बीआईएफआर नोटिस जारी करता है और जांच शुरू करता है। विनियम 20 के तहत 'जांच के संबंध में' अतिरिक्त जानकारी की मांग करना या केवल तब जब विनियम 21 के तहत बीआईएफआर द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं, धारा 16(1) के साथ पढ़ें। परिणाम यह है कि, 24.3.1994 को विनियम 19(5) के संशोधन के बाद, विनियम 19(5) का उत्तरार्ध विनियमों के अध्याय III और IV में आता है, जो कि धारा 16 के तहत 'पूछताछ' के संदर्भ में हैं। अध्याय II के बजाय अधिनियम, जो धारा 15 के तहत 'संदर्भों' से संबंधित है। हमारी राय में, अध्याय शीर्षकों को कठोर खंडों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इसलिए, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि 24.3.1994 से विनियम 19 में संशोधन के बाद, एक बार संदर्भ पंजीकृत होने के बाद और जब एक बार मुखबिर से सूचना/दस्तावेज मंगाना अनिवार्य है और ऐसा निर्देश दिया जाता है, तो धारा 16(1) के तहत जांच-धारा 22 के प्रयोजनों के लिए - शुरू मानी जानी चाहिए। धारा 22 और उसमें निहित निषेध तुरंत लागू होंगे। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमें कलकत्ता, राजस्थान और बॉम्बे उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए

दृष्टिकोण की सत्यता पर जाने की आवश्यकता नहीं है, जो असंशोधित विनियमन 19 पर निर्भर था। बिंदु 2 तदनुसार तय किया गया है। इस मामले के तथ्यों पर, 24.7.1997 को बीआईएफआर की कार्यवाही विनियमन 19(5) के दूसरे भाग के चरण में पहुंचने के बाद उच्च न्यायालय के दिनांक 28.7.1997 और 8.8.1997 के आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं, अर्थात्, जब संशोधित विनियम 19(5) के अनुसार कार्यवाही, धारा 16(1) के तहत जांच के स्तर पर पहुंच गई। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि उक्त आदेश अवैध हैं और अधिनियम की धारा 22 में निहित निषेध का उल्लंघन हैं।

उपरोक्त कारणों से, डिवीजन बेंच द्वारा 28.7.97 को रिसीवर नियुक्त करने का पारित आदेश और 8.8.97 को उच्च न्यायालय की एक अन्य बेंच द्वारा अनंतिम परिसमापक को बहाल करने का पारित आदेश रद्द किया जाता है। तदनुसार सिविल अपीलें स्वीकार की जाती हैं। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा। उत्तरदाता, यदि आवश्यक हो, इस संबंध में बीआईएफआर द्वारा पहले से पारित आदेशों के अलावा, आगे के आदेश, यदि कोई हो, के लिए अधिनियम की धारा 22 और धारा 22 ए के तहत बीआईएफआर से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आर.पी.

अपीलों की अनुमति दी गई।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री **अनुभव तिवाड़ी** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)